मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

फॉर्म हाउस गिराने का यही है बेहतरीन समय 3
नताशा, देवांगना व आसिफ...मजबूत लोकतंत्र की निशानी 4
जुनैद की हत्या आरोपी पुलिस पर कोई एक्शन नहीं 5
संघ के चम्पत राय एक गंभीर आरोप में घिरे 6
श्रीराम सोसाइटी का कथित प्रशासक गायब 8

वर्ष 34 | अंक 32 | फरीदाबाद | 20-26 जून 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

पुनर्वास बिना विध्वंस...यानी खोरी में गरीबों को सजा-ए-मौत

आखिरी उम्मीद टूटी, जिन्हें वोट दिया, वो झांकने भी न आए

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: अरावली जोन में खोरी-लकड़पुर में करीब दस लाख (10 हजार मकान) को उजड़ने से अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 17 जनवरी को एक याचिका दायर कर एमसीएफ का प्रस्तावित अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने और पुनर्वास की मांग की गई। अदालत ने किसी भी तरह का स्टे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि पुनर्वास करना सरकार का काम है। वो जाने। ...और वाकई हरियाणा की भाजपा सरकार इस समय सबकुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। उसके सांसद और विधायक एक बार भी खोरी गांव में किसी तरह का भरोसा देने नहीं पहुंचे। यही वो लोग हैं जो कोरोना काल में यहां बीजेपी के झंडे तले मास्क बांट कर सहानुभूति बटोर रहे थे और यहां की जनता भी मोदी-मोदी कर रही थी। अब खुद के ठगे जाने का एहसास हो रहा है। साथ कोई नहीं खड़ा है। साथ खड़े होने के नाम पर मेधा पाटकर और चंद अनजान एक्टिविस्ट हैं, जो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं।

ट्रांजिट कैंप बनाने में दिक्कत क्या है

फरीदाबाद जिला प्रशासन और एमसीएफ यहां रोजाना दबाव बना रहा है। किसी भी समय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। एमसीएफ को डेढ़ महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक हफ्ता निकल चुका है। प्रशासन डर दिखाकर यहां से लोगों को निकलने के लिए कह रहा है। उसकी यह तरकीब कारगर है। अभी तक 70 फीसदी से ज्यादा लोग अपना सामान वगैरह यहां से हटा चुके हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा अभी तक राहत कैंप या ट्रांजिट कैंप नहीं लगाने पर है। जब आप एक साथ दस लाख लोगों को यहां से बेघर कर रहे हैं तो वे सारे लोग किसी एक दिशा में एक साथ तो जा नहीं सकते। इसीलिए जब इतनी बड़ी आबादी का विस्थापन होता है तो ट्रांजिट कैंप लगाए जाते हैं। जहां से धीरे-धीरे लोग अपने नए ठिकानों की तरफ प्रस्थान करते हैं। आईएएस अफसरों को बाबूगीरी करने के अलावा मानवता का पाठ भी आईएएस अकादमी में पढ़ाया जाता है लेकिन लगता है कि वे अपना पाठ भूल चुके हैं। उन्हें यहां रोते-बिलखते लोग नहीं दिख रहे। उन्हें भावशून्य युवक तक नजर नहीं आ रहे।

डीसी साहब आपका प्लान कहां है

यह तय है कि खोरी अब उजड़ेगा। लेकिन अतिक्रमण हटाने की शुरुआत किस तरफ से होगी, उसकी रूपरेखा जिला प्रशासन ने मीडिया के सामने कम से कम स्पष्ट नहीं की है। प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है और सारी जिम्मेदारी पुलिस और एमसीएफ पर डाल दी है। रोजाना ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण

शेष पेज दो पर

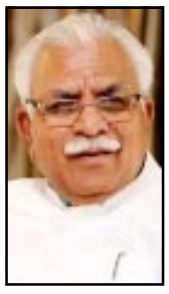

खोरी पर बोले सीएम खट्टर...

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को खोरी के मुद्दे पर अपने बयान में कहा कि अदालत का आदेश है तो खोरी से कब्जे हटाने ही होंगे लेकिन वहां से हटाये जा रहे लोगों के पुनर्वास पर पर भी सरकार चर्चा कर रही है। सीएम के इस बयान से खोरी गांव के लोगों को कोई राहत फिलहाल मिलने नहीं जा रही है। सीएम ने पुनर्वास के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी।

मेधा पाटकर पहुंची खोरी

जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर शुक्रवार को खोरी में वहां के लोगों के साथ अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने पहुंची। मेधा ने वहां कहा कि खोरी के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इस लड़ाई में मैं शामिल हूं और हर मंच पर यहां का मुद्दा उठाऊंगी।

गम्भीर चेतावनी

बड़खल झील का स्थाई सत्यानाश करने हेतु 83 करोड़ का बजट

पर्यटन विभाग के होटल-रेस्तरां तो क्या, मीलों तक बदबू फैलेगी

फ़रीदाबाद (म.मो.) बड़खल विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ते वक्त 2014 में सीमा त्रिखा ने बड़े ज़ोर-शोर से घोषणा की थी कि चुनाव जीतने के बाद यदि उनकी सरकार बनी तो वे बड़खल झील को जीवित करने के लिये इसे लबालब पानी से भरवा देंगी। वे दो बार चुनाव भी जीत गयी, उनकी सरकार भी बन गयी, परन्तु बड़खल आज भी अपनी बेनूरी पर रो रही है। झील समतल मैदान बन चुका है बड़खल गांव के बच्चे उसमें क्रिकेट खेलते हैं तथा आस-पास कंटीली कीकरों का जंगल बनता जा रहा है।

दरअसल जिस गिरोह के हाथ में सत्ता है, उसकी पहली प्राथमिकता जनहित न होकर सदैव जनता के धन को डकारने की रहती है। इसलिये वे लोग ऐसी जबरदस्त योजनायें बनाकर पेश करते हैं जिस पर मोटा खर्च दिखाया जा सके, जाहिर है जब खर्च का बजट मोटा होगा तभी तो उसमें सेंधमारी मोटी हो सकेगी। दूसरी ओर कुछ जनहितैषी एवं पर्यावरण प्रेमी होते हैं जो सस्ते एवं सुलभ उपायों द्वारा प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के निकट रख कर विकसित करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही एक पर्यावरण प्रेमी संगठन 'ग्रीन इन्डिया फ़ाऊंडेशन ट्रस्ट' के करीब 40 विशेषज्ञों ने पहली जून 2019 को बड़खल झील का दौरा किया। इस टीम में अलीगढ़ के सुबोध नंदन शर्मा, विख्यात पक्षी प्रेमी एआर रहमानी सहित कई अन्य जल, जंगल एवं प्रकृति प्रेमी विशेषज्ञ थे। इस संगठन के संगरक्षक मेग सॉय-सॉय पुरस्कार से सम्मानित जल पुरूष राजेन्द्र सिंह हैं।

इन सभी वरिष्ठ विशेषज्ञों ने 10-12 घंटे पूरे क्षेत्र में घूम-फ़िर कर यहां की प्रकृति, वनस्पति, पक्षियों आदि का जायजा लिया। इनहोंने पाया कि इस झील को बहुत आसानी से पुन: बरसाती पानी से ठीक वैसे ही भरा जा सकता है जैसे कि यह पहले भरी जाती रही है। इसके लिये पहाड़ से आने वाले बरसाती पानी के रास्ते में जो भी रुकावटें आ गयी हैं उन्हें दूर किया जाये जिससे बरसाती पानी बह कर झील तक आ सके। उनकी इस परियोजना पर सरकार का एक पैसा भी खर्च होने वाला नहीं था। इस संगठन के मुताबिक बड़खल झील की खुदाई से जो मिट्टी निकलेगी उसकी बिक्री से ही सारा खर्च निकल जायेगा।

यह सारा प्रपोज़ल न केवल लिख कर मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को दिया गया, बल्कि उक्त टीम ने अपने दौरे के समय विधायक सीमा त्रिखा को मौके पर भी बुलाया था। इतना ही नहीं 9 सितम्बर 2019 को इसी संगठन ने बड़खल झील पर एक कार्यक्रम आयोजित करके 1500 स्कूली बच्चों को प्रकृति, वनस्पति, पर्यावरण एवं झील के बारे में समझाया था ताकि बच्चे भी इसके महत्व को समझ सकें।

इस अवसर पर जलपुरुष राजेन्द्र सिंह व चंडीगढ की सुखना झील के निर्माता अशोक प्रधान (पूर्व आईएएस) ने भी इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया था।

परन्तु मुफ़्त के कामों में तो शासक गिरोह की कोई रुचि होती नहीं क्योंकि इससे तो उन्हें कुछ मिलने वाला होता नहीं, लिहाज़ा पर्यावरण विशेषज्ञों की योजना की ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी बजाय 83 करोड़ का बजट बना कर सीवर के सड़े हुए पानी से इस झील को भरा जायेगा। इसके लिये कई किलो मीटर लम्बी पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं। तीस एमएलडी का एक एसटीपी यानी सीवेज शोधन प्लांट सेक्टर 21 ए में रेलवे लाइन के निकट लगाया जा रहा है। ख्याली पुलाव पका कर 83 करोड़ का बजट ठिकाने लगाने वाले स्मार्ट लोगों का दावा है कि एसटीपी द्वारा शोधित जल बिल्कुल साफ़ एवं दुर्गंध रहित होगा। पूछने पर ये लोग कहते हैं कि उस पानी से कुल्ला करना तो क्या उसमें हाथ डालना भी संभव नहीं होगा। इतना ही नहीं इस गंदे पानी को धरती के भीतर समाने से रोकने के लिये प्लास्टर ऑफ़ पेरिस की एक परत भी जमाई जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस झील से कभी भूजल स्तर चार्ज होता था अब नहीं होगा।

सुधी पाठक इस बात को भली भांति समझ लें कि दिल्ली के तमाम नालों का जो सीवेज यमुना में गिरता है वह भी एसटीपी द्वारा संशोधित ही होता है उसके बावजूद स्वयं यमुना और इससे निकलने वाली आगरा व गुड़गांव नहर का सड़ा हुआ पानी देखा जा सकता है। दूसरा बढिया उदाहरण तिगांव रोड पर जेल के निकट बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। इसके दो किलोमीटर दायरे में दुर्गंध के मारे सांस लेना भी दूभर है। यदि समय रहते फ़रीदाबाद निवासी, खास कर बड़खल झील के आस-पास वाले, नहीं जागे और इस झील को सीवेज से भर दिया गया तो उनका वहां रहना तक दूभर हो जायेगा।